अध्यक्ष महोदय : पंजाब की शिकायत तो नहीं है ।

Shri A. M. Thomas: It is reported that in many States, there is much illegitimate use of gur and illicit distillation is one of the reasons why the gur prices are at a high level. There are reports like that.

Shri A. P. Jain: Is it a fact that when the ban was imposed, the U.P. Government insisted that once it is imposed, it should not be lifted until the end of the season for the reason that the gur would have passed into the hands of the middleman who will profit if this ban is lifted?

Shri A. M. Thomas: That has been the Central Government's view also. Otherwise, it would be quite unfair and it would be encouraging cornering of stocks by middlemen. Not only that. Even though the season is coming to an end, we do not propose to lift the ban because it will not benefit the grower, but it will benefit only the middlemen.

रेलवे स्कूल और कालिज

*६३०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलव क्षेत्रों (जोनों) में वर्तमान स्कूलों और कालिजों के अतिरिक्त भी कुछ और स्कूल तथा कालिज खोलने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलों द्वारा चलाये गये वर्तमान स्कूलों और कालिजों की देख-रेख के लिए कोई शिक्षा विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

संविधान में शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है और अन्य नागरिकों के साथ रेल कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठाते हैं । अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए, कर्मचारी-हित-सम्बन्धी काम के रूप में, रेलें कई स्थानों पर प्राइमरी, मिडिल, हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर के स्कूल चला रही हैं । ये स्कूल उन स्थानों में खोले गये हैं, जहां कोई स्कूल नहीं हैं या जहां अपेक्षित स्तर के स्कूल नहीं हैं या ऐसे स्कूल रेलवे बस्तियों से बहुत दूर हैं ।

वर्तमान नीति के अनुसार रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएं हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तर तक सीमित हैं । अतः रेलों ने अभी तक कालेज स्तर की शिक्षा देने का काम अपने हाथ में नहीं लिया है । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी पुनर्गठन-योजना के अनुसार टूंडला और मुगलसराय के दो रेलवे हाई स्कूलों को इन्टरमीडिएट स्तर तक बढ़ा कर उनमें ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाएं खोलनी पड़ी हैं ।

रेलें प्राइवेट प्रबन्धकों की भांति ही स्कूल चलाती हैं और कई स्कूलों के लिए उन्हें राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है । राज्य सरकारों के शिक्षा अधिकारी रेलवे स्कूलों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करते हैं । रेलवे स्कूलों से सम्बन्धित मामलों की देखभाल रेलों के मुख्य कार्मिक अफसर द्वारा की जाती है । स्कूलों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन कार्य के लिए रेलवे अफसरों को नियंत्रक अफसर नामित किया जाता है । ये अफसर प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका के जरिये प्रशासन कार्य चलाते हैं ।

परीक्षण के रूप में शिक्षा अधिकारियों के दो अस्थायी पद मंजूर किये गये हैं, एक पश्चिम रेलवे के लिए और एक दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए । पश्चिम रेलवे में इस पद पर

जो अफसर रखे गये हैं वह राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं और दक्षिण-पूर्व रेलवे में इस पद पर रेलवे के एक कार्मिक अफसर को लगाया गया है ।

नये स्कूल खोलने के सम्बन्ध में वर्तमान नीति यह है कि राज्य सरकारों से स्कूल खोलने के लिए कहा जाय और जहां राज्य सरकार स्कूल न खोलना चाहें, वहां रेल कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा के हित में स्कूल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय । ऐसे स्कूलों के लिए रेल प्रशासन नाममात्र किराय पर जमीन या इमारत और रेलवे राजस्व से सहायक अनुदान जैसी सुविधाएं देते हैं । यद्यपि इस नीति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में और अधिक स्कूल खोलने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है, फिर भी नये स्कूल खोलने के प्रस्तावों पर हर एक की स्थिति के अनुसार विचार किया जाता है और उन पर उचित कार्रवाई की जाती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कुल मिला कर इस समय रेलवे की ओर से कितने स्कूल और कालेज चलाये जा रहे हैं और उन में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वर्ष में कितना व्यय आप उन पर करते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : इस वक्त रेलवे के ७१५ स्कूल हैं और उन में १ लाख ४७५ तालिबइल्म पढ़ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कितना खर्चा करते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : खर्चे का कोई एग्जक्ट अनुमान मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि एक लाख से ऊपर विद्यार्थी रेलवे के स्कूलों में पढ़ते हैं । विवरण को देखने से पता लगता है कि एजुकेशन का कोई एक्सपर्ट इनको देखने के लिए नहीं रखा गया है, केवल विभाग के अधिकारी ही इनकी देख-रेख करते हैं । पश्चिमी रेलवे में केवल एक व्यक्ति इस प्रकार का है जो देख-रेख करता है । अगर रेलवे के पास कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है तो क्यों नहीं रेलवे सेंटर की एजुकेशन मिनिस्ट्री से कोई इस प्रकार का स्पेशालिस्ट ले लेती जिस की देख रेख में शिक्षा सम्बन्धी सभी काम चले, क्यों विभाग के अधिकारियों द्वारा ही यह सारा काम कराया जा रहा है ?

श्री त्यागी : टिकट कलैक्टर करते हैं यह काम ?

श्री शाहनवाज खां : मुअज्जिज मैम्बर को पता होगा कि एजुकेशन स्टेट की जिम्मेवारी है । हम चाहते हैं कि जितने स्कूल रेलवे के चलते हैं वे स्टेट एजकेशनल आथोरिटीज के जरिये से ही चलें । जहां कहीं रेलवे स्कूल चलते हैं तो वे वैसे ही चलते हैं जैसे प्राइवेट मैनेजमेंट के स्कूल चलते हैं । जो उनका सिलेबस होता है वह वही होता है जो स्टेट गवर्नमेंट तय करती है । स्टेट गवर्नमेंट के इंस्पैक्टर्ज आफ स्कूल्ज आ कर उनकी इंस्पैक्शन करते हैं । हम उनके मश्विरे के ऊपर ही चलते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्र : साढ़े सात सौ स्कूल हों और उन में एक लाख से ऊपर बच्चे पढ़ते हों, लेकिन शिक्षा का जानकार कोई न हो, एक्सपर्ट कोई न हो, यह आश्चर्य की बात है । अगर आपके पास एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप डेपुटेशन पर एजुकेशन मिनिस्ट्री से क्यों नहीं लेते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : उन स्कूलों में जो भी टीचर्ज रखे जाते हैं वे सब ट्रेंड टीचर्ज होते हैं, बी० ए० बी० टी०, एम० ए० बी० टी० आदि होते हैं । जो स्टेट एजुकेशनल आथोरिटीज हैं, उनकी जेर निगरानी ये स्कूल काम करते हैं ।

Shri Hari Vishnu Kamath: The statement laid on the Table of the

House says that although there is no specific proposal to open more schools in different railway zones in accordance with this policy, yet proposals regarding opening of new schools are considered on the merits of each case and suitable action is being taken thereon. May I know what are the criteria for judging the merits of each case and whether all these new schools will be distributed among the zones on a fair and equitable basis?

Shri Shahnawaz Khan: The criterion is that proper educational facilities for the children of railway employees must be provided. Whether the State Government provides it or not, it is a matter of convenience and the actual situation. If in the vicinity of a railway station or railway colony, State-run educational institutions are available, then we prefer that they should receive education through the State sources. But where railway colonies are situated in far-off distances where there are no privately run schools and colleges, the railway administration does not shirk its responsibility to provide suitable education.

Shri Hari Vishnu Kamath: The second part of my question has not been answered. Will the new schools be distributed among the zones on a fair and equitable basis?

Shri Shahnawaz Khan: These schools are distributed wherever they are required.

श्री राम सेवक यादव : जो मंत्री महोदय ने बयान सभा-पटल पर रखा है उसमें कहा गया है कि पश्चिमी रेलवे द्वारा वहांकी राज्य सरकार से एक शिक्षा अधिकारी बुलाया गया है डेपुटेशन पर । मैं जानना चाहता हूं कि उनको बुलाने का कारण क्या है और यदि शिक्षा क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए उसको बुलाया गया है तो फिर दूसरी जोंज में ऐसी व्यवस्था न करने का कारण क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : यह तजरबे के तौर पर हमने किया है । अगर उसके नतीजे अच्छे निकले और उससे कोई बहुत फर्क पड़ा तो बहुत मुमकिन है कि हम उसको बढ़ायें । मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि एक स्कूल ओक ग्रोव मसूरी में रेलवे का चल रहा है जिसमें लगभग छ सौ बच्चे पढ़ रहे हैं । एक रेलवे का अफसर उस स्कूल का प्रिंसिपल है । मैं माननीय सदस्यों को दावत देता हूं कि वे जाकर देखें उस स्कूल को और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के बेहतरीन स्कूलों में से वह स्कूल है ।

Shri D. C. Sharma: It is the policy of the railways not to open colleges. This is what is stated in the statement. May I know if the college-going children of the railway employees are given any stipends by the Railway Ministry?

Shri Shahnawaz Khan: Every year the Railways give 1000 scholarships for technical education to the children of railway employees and the children going to colleges are also eligible to get those scholarships.

Shri P. Venkatasubbaiah: In the statement laid on the Table the Railway Administration has confined itself only to high school education. May I know whether they consider the desirability of providing both technical and college education to such of the children of railway employees as have no facilities for college education?

Shri Shahnawaz Khan: We assist them from the Staff Benefit Fund.

श्री यशपाल सिंह: एजुकेशन अधिकारी होने के कारण अलग अलग स्कूलों के कोसिस मुख्तलिफ होते हैं और जब एक रेलवे अफसर का दूसरी जगह तबादला होता है तो उनके बच्चों की पहले की पढ़ी हुई किताबें बेकार हो जाती हैं और उनको नए सिरे से जाकर

फिर पढ़ना पड़ता है और दिक्कत उठानी पड़ती है, क्या यह सही है ?

श्री शाहनवाज खां : यह समस्या सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के लिए नहीं है बल्कि तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लायीज हैं, उनके लिए है । हर एक सूबे का अलहदा अलहदा शिक्षा का प्रोग्राम है और वह एजुकेशन मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली चीज है न कि हमसे ।

श्री बड़े : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि केवल एक स्कूल बेहतरीन लाइंज पर चलता है । क्या इसका मतलब यह है कि बाकी के जो साढे सात सौ के करीब स्कूल हैं, वे बेहतरीन लाइंज पर नहीं चलते हैं या वहां पर कुछ गड़बड़ियां हैं ? क्या आपके पास कुछ ऐसी भी कम्प्लेंट्स आई हैं कि वहां पर टीचर्स का एप्वाइंटमेंट बराबर नहीं होता है ?

श्री शाहनवाज खां इतनी बड़ी तादाद में जब स्कूल हैं तो मुमकिन है कि कहीं इन्तजाम बहुत अच्छा न हो । लेकिन अगर माननीय सदस्य बतायेंगे कि कहां इन्तजाम ठीक नहीं है तो मैं उसके ऊपर तवज्जह दूंगा ।

श्री तुलशीदास जाधव : रेलवे मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तो उनसे जो फीस ली जाती है वह उनके पेरेंट्स के पगार के हिसाब से ली जाती है या एक सी फीस सब से ली जाती है ? उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का भी क्या कोई इंतजाम आपने किया है ?

श्री शाहनवाज खां : प्राइमरी स्कूल तक की एजुकेशन मुफ्त है ।

Shri S. C. Samanta: Is it not a fact that due to continuous overflow of students in the Kharagpur Higher Secondary School every year a second school has been opened by the employees there; if so, may I know whether the facilities mentioned in the statement are being given to that institution also?

Shri Shahnawaz Khan: In fact, we welcome the opening and running of schools by the employees themselves under their own arrangement, and we subsidise them by giving them plots of land, buildings and also some financial aid.

Shri Daljit Singh: May I know what special facilities are provided to the students in these schools and colleges?

Shri Shahnawaz Khan: Up to the primary standard the education is free. We give scholarships for technical education. In the staff benefit fund also there is a committee which gives assistance to the deserving cases.

Escape of Mr. Walcott

*932. **Shri Hari Vishnu Kamath:** Will the Minister of **Transport** be pleased to refer to the reply given to Starred Questions Nos. 6 and 394 on the 11th February, 1964 and 3rd March, 1964 respectively and state:

(a) whether the inquiry regarding the escape of Mr. Walcott from Safdarjang Airport on the 26th September, 1963 has been completed;

(b) if so, the findings and conclusions thereof; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the stage which it has reached?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Mohiuddin): (a) to (c). The investigation by the officer appointed to further enquire into the escape of Mr. Walcott is still in progress.